स्वतन्त्रता की भ्रोर "टुबर्ड फीडम" परियोजना के लिए स्रोतों का संकलन, भीर स्वाधीनता पूर्व के राजसी राज्यों में प्रजा मण्डल भ्रान्दोलन।

- (ग) 1974-75, 1975-76 मौर 1976-77 के दौरान परिषद को दिये गये ग्रनुदान कमश: 21.22, 32.27 मौर 33.86 लाख रुपये हैं।
- (घ) भौर (ङ) परिषद के प्रथम अध्यक्ष का कार्यकाल मार्च, 1977 में समाप्त हो गया। नये अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, परिषद के निदेशक से अध्यक्ष के वर्तमान कार्य सभालने का अनुरोध किया गया है।

फूड फौर वर्क योजना के झन्तर्गत बिहार को खाखान्न की सप्लाई

2636. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव : क्या कृषि ग्रीर सिंखाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा फूड फौर वर्क योजना के बन्तर्गत बिहार राज्य को कितने टन गैं इंदिया जाएगा।
- (ख) क्या बिहार राज्य ने इस योजना के ग्रन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का विकास कार्य शुरू करने का निर्णय किया है; ग्रीर
- (ग) यदि हां, तो इस योजना के भ्रन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को कितनी अविध तक रोजगार दिये जाने की सम्भावना है ?

हृषि ग्रीर सिंबाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मानु प्रताप सिंह): (क) विहार 2812 LS—8. सरकार को 'कार्य के लिए भोजन' योजना के मन्तर्गत लघु सिंचाई परियोजनामों के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 मीटरी टन गेहं मादन्टित किया गया है।

(ख) भीर (ग). राज्य सरकार ने सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु मिट्टी का कार्य शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा था। उन्हें अधिक समय तक चलने वाली सड़कों भर्यात पक्की सड़कों का निर्माण करने की सलाह दी जा रही है। चालू वर्ष में 118 लाख श्रम दिनों का रोजगार पैदा करने की संभावना है। 'कार्य के लिए भोजन' योजना श्रम की भावस्थकता तथा उपलब्धता पर निर्मर करते हुए वर्ष के किसी भाग के दौरान चलाई जा सकती है।

बिहार में बर्मा तथा बांगला देश के बिल्या-पितों की हालत का प्रप्ययन करने के लिए दल

2637. भी जानेश्वर प्रसाद यादव: क्या निर्माण, भीर भावास तथा पूर्त भीर पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बर्मा एवं बंगलादेश से आये विस्थापितों की, जो बिहार के पूर्णिया कटिहार एवं सहरसा जिलों में भा कर बस गये है, हालत का भ्रष्ट्ययन करने के लिए कोई दल बिहार भेजा है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें कुठ दिशेष सुविधाएं देने का है; स्रोर
- (ग) क्या विस्थापितों की माथिक स्थिति संतोषजनक नहीं है ?

ुनक्रीत और भावास तथा पूर्ति और पुनक्रीत मंद्रालय में राज्य मंद्रा (भी राम किकर): (क) से (ग). जी, हां। सरकारी दल 9 नवम्बर, 1977 को वापिस भा गया और उसने प्रथनी रिपोर्ट हाल ही में सरकार के विचार के लिए प्रस्तुत की है।

Reasons for Deterioration in Working Efficiency of D.M.C. Delhi

2638. SHRI MANORANJAN BHAK-TA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND RE-HABILITATION be pleased to state:

- (a) whether the Municipal Corporation of Delhi is facing financial crisis for quite some time;
 - (b) if so, full facts and reasons;
- (c) whether due to this civic services like repairing of roads, water mains have deteriorated in the capital; and
- (d) if so, steps being taken by Government to look into the working of the DMC and streamline its working and the changes proposed in its present set up?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND RE-HABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) to (c). Financial difficulties of the Corporation were brought to the notice of the Government shortly after the reconstitution of the Municipal Corporation after election and loan assistance sought to meet the additional expendtiure on D.A. to the staff, payment of arrears to teachers, payment of bills to contractors, etc. The Ministry of Home Affairs sanctioned ways and means advance of Rs. 2.5 crores in November, 1977. Various civic services are being maintained within the resources available with the Corporation: During the current year there has been extensive damage to

Municipal Roads and other properties and steps are being taken to undertake the repairs.

(d) The Government had appointed a Committee in January 1976 to examine the financial position of Municipal Corporation of Delhi. The report of the Committee, is under consideration of Delhi Administration. No specific proposal for changing the set-up of the Municipal Corporation of Delhi is being considered.

Meeting on Land Reform held in November, 1977

2639. SHRI MANORANJAN BHA-KTA: Will the Minister of AGRICUL-TURE AND IRRIGATION be pleased to state:

- (a) whether a meeting on land reforms has taken place in November 1977 with the State Minister;
- (b) if so, major issues discussed at the said meeting and the decisions taken thereon; and
- (c) plans worked out to boost the agricultural production and improve the lot of farmers?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Yes, a meeting of the Central Land Reforms Committee was held on 2-11-1977 which was attended, among others, by some of the Ministers and senior officers in charge of Land Reforms Programmes in the States,

(b) and (c). At the meeting it was agreed that the implementation of Land reforms programmes should be accelerated and vigorous action should be taken to identify and remove the legal and procedural bottlenecks. It was also agreed that the lands that have become available on imposition of ceiling in the States should be expeditiously allotted to cultivating tenants and landless persons. It was also agreed that efforts should be made to